

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अगर सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या आप तैयार हैं ?

SHRI M. M. JACOB: Sir, if the banks are prepared to foot the bill, it is a note proposal and we have to consider it.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Balaram.

SHRI N. E. BALARAM: Sir, I am not suggesting setting up of a special security force for the banks. Now, there are certain areas considered very vulnerable. So, special protection has to be given to these areas. What is the idea of the Government with regard to giving special protection to such areas ? I am asking this question because the Minister was saying that the thinking of management of the banks was that they would manage their security. But what happened in Okhla was that the robbers first shot down all the security people and then they entered, the banks and attacked all the employees. So, it has been proved that the banks cannot have their own security people. Since there are certain very vulnerable areas. I would like to know from the Minister what special measures the Government is proposing to take for the protection of the banks and bank employees in such areas.

SHRI M. M. JACOB: Sir, twice the Government had sent special instructions to the concerned States and asked them to follow certain formalities in this connection. For example, the last one was on the 3rd June 1991, The Home Secretary issued instructions to the Chief Secretaries of Nagaland, Manipur, Tripura and Punjab in which they were informed of what steps the banks should take and the State Governments also should take. But some places we have found, particularly in vulnerable areas, that when you carry cash from one bank to another, dacoities take place. Therefore, we have to provide the support of security personnel and CRPF men are also to be deployed for this purpose. These things happen in the banks in certain vulnerable areas. We have informed them of the use of wire net, etc. and certain other parameters of protection are also given in the

guidelines and these guidelines are passed on to the Chief Secretaries and they are adhering to them as far as our information goes.

MR. CHAIRMAN: Question No. 242.

Proposal to meter the local calls every three minutes

*242. SHRI RAMSINH RATHWA:

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that MTNL has sent a proposal to Government of India to meter the local calls in Delhi and Bombay every three minutes per calls: and

(b) if so, what are the arguments in support of the proposal and Govt.s reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) The proposed scheme is to meter the local call once in 3 minutes. Timed metering of local calls is expected, to encourage the subscribers to limit the duration of calls thereby enabling the common equipment available to carry more traffic. The Exchanges will get de-congested and the call completion rate is likely to increase leading to greater subscriber satisfaction.

The proposal is under consideration of the Government.

श्री राम सिंह राठवा : माननीय सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को लाने से पहले पार्लियामेंटरी कंसल्टेटिव कमेटी के साथ या दूसरे कोई संगठन के साथ या दूसरी संस्थाओं के साथ टेलीफोन

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramsinh Rathwa.

सेवा सुधार के लिए कोई सजेशन मांगे थे? अगर कोई टेलीफोन सेवा सुधार के लिए सजेशन आए हैं तो वे क्या-क्या थे? जहाँ तक तीन मिनट की जो बात है, उसमें तीन मिनट कैसे काउण्ट किए जाएंगे? मैं थोड़ा सा इस बारे में स्पष्टीकरण जानना चाहता हूँ। मान लो, किसी एक जगह से मेरे पास टेलीफोन आया और मैं वह टेलीफोन सुनना नहीं चाहता। मैंने रिसीवर उठाकर साइड में रख दिया और अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन सामने वाला सोचता है कि देखें बोलता है या नहीं। अब चूँकि मैंने रिसीवर साथ में रख दिया है और कोई जवाब नहीं है, सामने वाला रिसीवर नहीं रखता है तो तीन मिनट आप कैसे काउण्ट करेंगे? क्या जब जवाब मिलेगा तब से या नहीं मिला तब से? या फिर आधा घंटा तक मैं बाहर रिसीवर रखा, तब से? इसके बारे में मंत्री महोदय जरा बताइए।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेश पायनट) : सर, यह सवाल पहले भी कई बार उठा और वर्ष 1980 से इस विषय पर कई बार चर्चा हुई। सदन में जो मेरे विभाग के मंत्री थे स्वर्गीय वीर बहादुर जी, उन्होंने भी इस सवाल का जवाब इसी रूप में दिया था और बाहर भी कई फोरम पर चर्चा हुई कि यह टाईमिंग तीन मिनट का करें या न करें। सर, कुछ सुझाव ऐसे थे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जितनी हैं वहाँ पर कंजेशन बढ़ गई और खासकर जैसे दिल्ली का उदाहरण है कि जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर हमारा कंजेशन 45 से 50 परसेंट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर है, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर कंजेशन नहीं है। एक यह विचार था कि सुविधा इससे सुधर सके और ज्यादा भाई ज्यादा संख्या में बात कर सकें। तो यह सुझाव एम०टी० एन० एल० डिपार्टमेंट के पास भेजा है, विचारार्थ है। इसमें मैं चाहूँ कि अगर माननीय सदस्य भी अपने विचार दे सकें तो दें, जिससे कि हम इसको उस रूप में लागू कर सकें।

श्री राम सिंह राठवा : माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसे तीन मिनट की पाबंदी अगर लागू की जाएगी

तो सभी मेम्बर आफ पार्लियामेंट के पास बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं और मेम्बर आफ पार्लियामेंट के लिए कुछ हद तक फ्री-कॉल है लेकिन जो आने वाले गेस्ट हमारे हैं उनकी अगर बात पूरी नहीं होती तो वह उसी बात के लिए दस बार कॉल करेगा। उसके लिए मंत्री महोदय बताएँगे कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट के फ्री-कॉल के बारे में आपने क्या सोचा है?

श्री राजेश पायनट : तो असली मुद्दा यह है। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : भाई, मेम्बर आफ पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट होते हैं।

श्री राजेश पायनट : सर, जब मीटिंग होगी तीन मिनट की तो हर काल तीन मिनट का होगा। वह दूसरी बात है कि जब मीटिंग होगी तो माननीय सदस्यों के कॉल की संख्या बढ़ाई जा पाएगी या नहीं बढ़ाई जा पाएगी। उसके लिए जैसा कि पार्लियामेंट का प्रोसीजर होगा, हम लोग पार्लियामेंटरी मिनिस्टर से डिस्कस करके, उसके बारे में जैसे सुझाव होंगे उनको लागू करने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : माननीय सभापति जी, बंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, जहाँ दूरभाष सर्वाधिक व्यस्त होता है, स्थानिक संभाषण उसकी समयावधि अमरियाद हो नहीं सकती। इसको समय की सीमा में बांधना निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन इसमें सबसे पहली समस्या यह है कि यह व्यवस्था केवल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में हो सकती है। पता नहीं मंत्री महोदय ने यह कैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के कारण व्यस्तता बढ़ गई है, मैं तो यह मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होने से व्यस्तता कम होती जाती है क्योंकि फोन जल्दी मिलना शुरू हो जाने है। खैर, सवाल इसमें सबसे पहले यह आता है कि यह तीन मिनट की समयावधि बंबई और दिल्ली में लागू होगी और बाकी देश की किसी ग्राहक को तीन मिनट का संबंध नहीं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होगा नहीं। उसके साथ मुंबई शहर में 48 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है और 52 प्रतिशत साधारण एक्सचेंज है। तो

48 प्रतिशत एक्सचेंज वाले लोग 3 मिनट प्रति काल पैसा देंगे और 52 प्रतिशत वाले लोग अगर घंटे भर भी बोलें तो उनका काल ही काल होगा। दिल्ली में यह प्रतिशत 67 और 23 का है। अब एक ही शहर में, एक ही काल का पर दो प्रकार की दर लगाना, मुझे लगता है कि यह कानून या न्याय के कितना संगत होगा, यह भी सोचना पड़ेगा और इसलिए पूरा प्रश्न दो हिस्सों में पूछना चाहूंगा। न्यायालय का मामला तो मंत्री जी स्वयं देख लेंगे कि यह उचित है या अनुचित है क्योंकि लोगों ने कहा कि हम इसके खिलाफ न्यायालय में जाएंगे वरना एक ही शहर में आप दो प्रकार की दर लगाने नहीं सकते। मेरे दो पूरा प्रश्न हैं, मैं इसमें समरसीम बांधने के पक्ष में हूँ। घंटों बात करने के लिए टेलीफोन का उपयोग नहीं होना चाहिए।

मेरे प्रश्न का (क) हिस्सा है कि 3 मिनट के पीछे क्या तक है? यह सदियों से चलता आया है कि 3 मिनट का एक काल होगा। क्या 3 मिनट में पूरी बात हो जाती है, उसका कोई सर्वेक्षण हुआ है? यह 3 मिनट कहाँ से आया? एक काल के लिए काल के लिए तो इन्होंने पहले से ही 3, 6, 9 और वंद, इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं यह चाहता हूँ कि स्थानिक काल के लिए 3 मिनट बहुत कम समय होगा क्योंकि कभी-कभी लोगों को आने में इतना समय लग जाता है कि 3 मिनट उसी में लग जाती है। तो क्या इस सीमा को बढ़ाने का विचार मंत्री महोदय करेंगे?

मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह कि एस टी डी की तीन प्रकार की दरें हैं—दिन में एक, शाम में अर्धा और रात में चौथाई। बिम्बई में महानगर टेलीफोन निगम से हमने पूछा कि क्या 3 मिनट प्रति काल आप लगाने, यह 24 घंटे चलेगा? उन्होंने उन्होंने कहा कि यह 24 घंटे के लिए लगेगा। अब मैं यह लगता है कि देश में कहीं भी या विदेश में कहीं भी अगर आप करें तो दिन में एक प्रकार की दर होती है, शाम में उससे अर्धी होती है और रात में अगर एक चौथाई होती है, तो अपने शहर में मीटरिंग करते समय 24 घंटे में 3 मिनट प्रति काल इस प्रकार से रखना यह अन्यायकारक होगा।

तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे एस टी डी में तीन दरें हैं, जैसे ही स्थानिक काल मीटर करते समय क्या तीन प्रकार की दरें महानगर टेलीफोन निगम लगाएगा जिसके कारण व्यस्तता का जो समय है, जैसा अपने कहा कि इंडस्ट्री, बिजनेस, उसके लिए कह रहे हैं क्योंकि वह रात में 12 बजे नहीं होता है। रात को 12 बजे फोन तो किसी घर से ही दूसरे घर में घरे में होगा। ... (व्यवधान)

श्री दीपेन घोष : कई देशों में रात के 12 बजे ... (व्यवधान) ...

श्री प्रमोद महानन : मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने देश की बात कर रहा हूँ। और इसलिए स्थानिक काल में अगर आप व्यस्तता का जो समय है—10.00 से 05.00, उसमें तो आप मीटर लग जाए लेकिन उसके बाद का था पहले का जो समय है कम से कम उसका मीटर चाँजिग अलग से हो। क्या मेरे यह दो सुझाव या प्रश्न आप जायज समझेंगे? इस पर आप विचार करेंगे?

श्री राजेश पायनट : सभापति जी, जहाँ तक 3 मिनट का सवाल है, यह 3 मिनट कैसे छूटे गए, असलियत तो मैं नहीं बत पाऊँगा कि 3 मिनट कैसे छूटे गए, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज है कि 3 मिनट को ऐसे व्यापक रूप से सोचा होगा कि 3 मिनट में एक सधारण आदमी आम बात कर सकता है।

श्री प्रमोद महानन : शायद भारतीय संसति में तीन बहुत जगह आता है।

श्री राजेश पायनट : दूसरी बात यह है कि आडवणी जी और प्रमोद जी 3 मिनट में बात नहीं कर पाएँगे, यह मैं भी मानता हूँ कि उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन इन्होंने सधारण रूप से देखा होगा कि एक नगरपालिका की 3 मिनट में बात हो जाती है। इन्होंने समझा होगा कि 3 मिनट में बात होगी।

यह सब अभी सुझाव है, सभापति जी, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और न हमने अभी यह फैसला लिया है कि यह एस टी डी रेट्स के हिसाब से होना चाहिए। अभी सभी तरह के सुझाव आ रहे हैं और जो प्रमोद जी

ने सुझाव दिए हैं, वे नोटे कर लिए हैं, इनको भी ध्यान में रखूंगा जब फैसला लूंगा।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: May I know from the hon. Minister whether he would consider to re-regularise the other metered calls like the STD and the ISD?

SHRI RAJESH PILOT: Re-regularising what?

श्री भुवनेश्वर कलिता : मैंने पूछा कि अभी जो आपने रेट्स लगए हैं एस टी डी और आई एस डी के लिए, उनको क्या रीरगुलराइज करेंगे दो अलग अलग हस्तों में ?

श्री राजेश पायलट : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधन नहीं है।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Sir, I am very much worried on this score because we have two sections of society. One is affluent which can afford and the other one falls in the category of middle class. I am sure the hon. Minister would appreciate that telephone is no longer a luxury. Now, I am coming to the point of corruption. Sir, when STD came into being, there has been a lot of corruption, the lines have been tampered with and when a middle class person who really cannot afford, who does not even know how to get into the channel of corruption, goes and complains he is simply told, "sorry, this is your STD charge". This is number one. And number two, it is very easy by a stroke of pen, you augment charges without considering the service level, I am fully appreciative of the situation that we have got to come to a solution because elsewhere in the world this has been the practice. But elsewhere in the world every charge has a service component attached to that. We totally ignore the service aspect. Now, I am coming back to my main question, of corruption. What are you going to do in case of that section which cannot afford and which does not know how to get into this rut of corruption. It is only the affluent section which can afford. They have all the rigmarole. They have all the strings.

Sir, are you going to consider how would you stop tampering? If you are going to install a meter it is only fair that under the conditions under which we are living in India, the meter should be installed in the subscriber's house. Are you going to consider this as well?

SHRI RAJESH PILOT: Sir, hon. Member has pointed out some faults in functioning where corruption could be pointed out. I do share his feeling that there are some lapses. I am not saying that there are no lapses. There have been efforts from the department side to counter them and we have been able to reduce them to a great degree. There are complaints when people get on to a different STD and the bill comes on some other number. These faults are in our mind. We have been working on it. I would be obliged if hon. Member can send his indepth study on the subject and help me on this.

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, घर में मीटर कैसे बिजली, पानी का होता है तो टेलीफोन का भी लगवाइये।

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: Sir, today, you pay Rs. 20 and you make a call anywhere in the world. This is a known fact. I am sure the hon. Minister would also know it.

SHRI RAJESH PILOT: I have accepted that. Sir, we are taking measures to find out. . . . (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: You can technically stop it.

SHRI RAJESH PILOT: Let me tell you one thing very frankly. There is only one possibility technically where you can monitor some calls. In electronic exchange we have been able to do it but on others we are finding some problems. ; But we are working on it. And we are losing revenue on this.

श्री प्रमोद महाजन : बिजली पानी सब का मीटर अगर घर में हो सकता है तो टेलीफोन का क्यों नहीं हो सकता ? हमारे सामने रहे मीटर।

SHRI RAJESH PILOT: I will see the feasibility.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, the facility of telephone is very laudable but it has led to increase in cost in our country. Now, you are introducing a system of three minutes duration for a call. It means we will be further burdened. We are already burdened. But whatever increase may be made in telephone lines, new connections are not being sanctioned. This is one. Second, my colleague has stated about three minutes facility. Particularly in India, there is a habit of talking particularly with women members of our family. That is a fact. Women members of the family have to perform so many duties.

MR. CHAIRMAN: Women Members of Parliament also.

SHRI A. G. KULKARNI: They have to talk to their daughters if they are in town. And if they are in a different town, they have to keep in contact. These are various difficulties. So, for Heaven's sake, don't consider the proposal of introducing 3-minute restriction as an improvement in the system at present. And you say that it is under consideration. But in Bombay, the MTNL has already notified that from 1st of September this will start. Please announce it today that it is being postponed to a later stage when the various problems and weaknesses are sorted out to the satisfaction of the subscribers and the Government.

SHRI RAJESH PILOT: As I have already said, this is just a proposal. No date has been announced; no decision has been taken and it is still under consideration of the Government. This was a proposal given by the MTNL to the Government. We are having the views from various sectors but we have not taken any decision that from 1st of September it will be implemented.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: But MTNL has already announced that from 1st September it will be implemented.

SHRI RAJESH PILOT: This was a suggestion which we have not cleared.

SHRI DIPEN GHOSH: How can he announce it?

SHRI A. G. KULKARNI: Am I to understand that this will not be implemented in Delhi and Bombay from 1st of September?

SHRI RAJESH PILOT: It will not be. That is just a proposal and it is not going to be implemented till the Government takes a decision on it.

SHRI DIPEN GHOSH: As I could understand from the reply of the Minister, they are considering it and the Government has not yet decided to introduce a system by which one can talk longer while paying more for it. My colleague, Mr. Pramod Mahajan, rightly said that it may run into a discriminatory system because there is a variety of systems in vogue today under various exchanges, electronic, cross-bar, strowger, manual and so on and so forth. My point is that because of the failure of the equipments and instruments, many calls are metered which are wrong calls and for that the subscriber is subjected to pay. I want to know whether the Government is considering to introduce a system by which wrong calls which are metered, should not be subject to payment by the subscriber. Will the Minister consider to pay back to the subscriber for the wrong calls which are metered?

SHRI RAJESH PILOT: There is already a procedure available in the department that if your bill has been metered wrongly there is a procedure and the money is repaid.

SHRI DIPEN GHOSH: I know that immediately the subscriber has to tell that this was a wrong call and this should not be metered. But it is a circuitous procedure. I have seen that calls given through the Assistance 199 also become wrong calls and they are metered. You must introduce some mechanism.

SHRI RAJESH PILOT: I have to check up technically how much is feasible.

243. [The questioners (Shri Pusumpon Tha Kiruttinan and Shri T. R. Balu) were absent. For answer vide col. 28 *infra*.]